Useful For Prelims

Date: 10 - 11 - 2025

संस्कृति और संवाद का जीवंत संगम है हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेला

शंकर सिंह • जागरण

सोनपुर : वैदिक श्लोकों की मंगल ध्वनि और पारंपरिक विधि-विधान के साथ रविवार की शाम विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का भव्य उद्घाटन हुआ। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सारण प्रमंडल के आयुक्त राजीव रौशन ने कहा कि समय के बदलते परिवेश में हमें संकल्प लेना चाहिए कि इस ऐतिहासिक मेले की गरिमा और गौरव को और बढ़ाएं। उन्होंने मोबाइल की आभासी दुनिया में डूबे लोगों की ओर संकेत करते हुए कहा कि 'यह मेला वास्तविक दुनिया से जुड़ने, संस्कृति को आत्मसात करने और विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच मिलन का अद्भुत मंच है।

आयुक्त ने कहा कि अब यह मेला केवल पशु मेला नहीं रह गया है, बल्कि इसमें हर वर्ष नए-नए

हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेले के मुख्य पंडाल मंच पर नृत्य प्रस्तुत करतीं कलाकार। • जागरण

आयाम जुड़ रहे हैं। उन्होंने हरिहर क्षेत्र के धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह स्थल हरि (विष्णु) और हर (शिव) की संयुक्त शक्ति का प्रतीक है। इस मेले का इतिहास गौरवशाली और प्रेरणादायक है। बदलते समय के साथ मेले को भी आधुनिक स्वरूप में ढालना होगा ताकि अधिक से अधिक लोग यहां आकर्षित हों।

मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व : डीआईजी : डीआईजी निलेश कुमार ने कहा कि हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। यह मेला बाबा हरिहरनाथ मंदिर के कारण विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जनकपुर जाते समय भगवान श्रीराम ने इसी स्थान पर हरिहरनाथ मंदिर की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होने के साथ-साथ ग्रामीण उत्पादों का प्रमुख बाजार भी है। यहां लोक कलाकारों को प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है।

मेले में लौटेगी घुड़दौड़ की परंपरा : जिलाधिकारी अमन समीर ने प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि इस बार मेले में बंद पड़ी घुड़दौड़ को पुनः शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही डाग शो, नौका दौड़, साहित्यिक कार्यक्रम और पुस्तक मेले का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला उभरते कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा निखारने का मंच है, और इस बार ऐसे कलाकारों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं, एसएसपी डा. कुमार आशीष ने मेले में की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी दी। समारोह के दौरान सभी अतिथियों को अंगवस्त्र, पौधा और बाबा हरिहरनाथ का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी, डीडीसी, एसएसबी कमांडेंट अभय प्रकाश, पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक, नजारत उपसमाहर्ता रवि प्रकाश, एडीएम मुकेश कुमार, अपर समाहर्ता सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह के अंत में धन्यवाद ज्ञापन एडीएम सारण ने किया। उद्घाटन के बाद सीआईएसएफ के जवानों ने आकर्षक बैंड वादन प्रस्तुत किया, जिसके बाद बिहार गौरव गांव कार्यक्रम की मनमोहक झांकी प्रस्तुत की गई।

Dainik Jagaran Patna City

मिस्र में पिरामिड के भीतर मिली 30 मीटर लंबी सुरंग

शारजाह, एजेंसी। मिस्र के पिरामिड के अंदर 30 मीटर लंबा गलियारा मिला है। यह गलियारा एक बंद दरवाजे की ओर जाता है। यह नई खोज प्रसिद्ध मिस्रविज्ञानी डॉ. जाही हवास ने की है।

उन्होंने घोषणा की है कि राजा खुफू के पिरामिड के अंदर एक नई पुरातात्विक खोज 2026 में दुनिया के सामने आएगी। उन्होंने बताया कि उन्नत स्कैनिंग तकनीकों का उपयोग करके खोजा गया 30 मीटर लंबा गलियारा शामिल है, जो एक बंद दरवाजे की ओर जाता है, जिससे प्राचीन मिस्र के इतिहास के एक अध्याय को फिर से लिखने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि उनकी यात्रा कानून का अध्ययन करने की महत्वाकांक्षा से शुरू हुई और फिर मिस्र विज्ञान के प्रति आजीवन जुनून में बदल गई।

Hindustan Page No-16

प्रमोद, कृष्णा व सुकांत ने लगाई पदकों की झड़ी

शिजुओका सिटी (जापान), प्रेट्र: स्टार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और सुकांत कदम ने रविवार को जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे भारत ने आधे दर्जन से अधिक स्वर्ण पदक जीते। भगत ने सिंगल्स, डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक जीता, जबकि टोक्यो पैरालिंपिक चैंपियन नागर ने सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक हासिल किए। सुकांत ने पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीतने के अलावा सिंगल्स में रजत पदक हासिल किया। भगत ने एसएल3 वर्ग में पुरुष सिंगल्स में जापान के दाइसुके फुजिहारा के विरुद्ध पहला गेम गंवाने और दूसरे में 16-19 से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए एक घंटे और 33 मिनट में 17-21, 21-19, 21-10 से जीत दर्ज की। पुरुष डबल्स में भगत ने सुकांत के साथ मिलकर जगदीश दिल्ली और नवीन शिवकुमार की हमवतन जोड़ी को 21-17, 18-21, 21-16 से हराया।

पदकों के साथ भारतीय पैरा शटलर

अंतरिक्ष में डेटा सेंटर से ग्रीन होगा डिजिटल रेवोल्यूशन

दुनियाभर में तेजी से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। आज के इस दौर में सिर्फ धरती पर ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है और समय के साथ नई-नई खोजें हो रही हैं। इसी बीच दुनिया के बड़े बिजनेसमैन और एमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस ने एक टेक्नोलॉजी की एक नई कल्पना को आकार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले 10 से 20 सालों में अंतरिक्ष में गीगावाट-स्तर के डेटा सेंटर बनाए जा सकते हैं।

अमेरिकी कम्पनियाँ कर रही हैं पहले से काम

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने के लिए कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। अंतरिक्ष में किसी डेटा सेंटर को लॉन्च करने की लागत बिलियन डॉलर्स तक जा सकती है। सर्वर-मेंटेनेंस, मरम्मत और सॉफ्टवेयर अपग्रेड जैसी सामान्य प्रक्रियाएं अंतरिक्ष में बेहद कठिन होंगी। इसके अलावा डेटा ट्रांसमिशन में लेटेंसी और संचार बाधाएं भी बड़ी समस्या होंगी। फिर भी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों के अध्ययन ने इस विचार को संभावनाओं से भरा और पर्यावरण-हितैषी बताया है। कई अमेरिकी कंपनियाँ पहले से ही छोटे प्रोटोटाइप पर काम भी कर रही हैं।

दुनिया को होगा फायदा

अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनने से भविष्य में पृथ्वी-आधारित सर्वरों की ऊर्जा-खपत में भारी कमी आएगी और मानवता के लिए एक ग्रीन डिजिटल रेवोल्यूशन की दिशा खुल सकती है। इसमें डेटा, ऊर्जा और अंतरिक्ष एक साथ नई टेक्नोलॉजी लिमिट को पार कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक डेटा सेंटरों को विश्व की कुल बिजली का लगभग 10% तक हिस्सा चाहिए होगा। इसी संकट से बचने के लिए अंतरिक्ष-आधारित डेटा सेंटर की परिकल्पना की जा रही है। अंतरिक्ष में लगातार 24 घंटे सौर ऊर्जा उपलब्ध रहती है वहां मौसमी अवरोध भी नहीं होते। इससे ऊर्जा-उपयोग अधिक कुशल हो सकता है। साथ ही अंतरिक्ष का अत्यधिक ठंडा वातावरण डेटा सर्वरों को ठंडा रखने में मदद कर सकता है, जिससे पानी और बिजली की भी बचत होगी।

तकनीक | कैलिफोर्निया के ऊपर परमाणु मिसाइल के परीक्षण के दौरान इसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई, नई परमाणु-सक्षम स्टैंडऑफ मिसाइल से काफी मिलती-जुलती

अमेरिका बना रहा अत्याधुनिक परमाणु क्रूज मिसाइल

नई दिल्ली। अमेरिकी सेना एक बहुत ही खास और गुप्त परमाणु मिसाइल बना रही है। इसे एजीएम-181ए लॉन्ग रेंज स्टैंडऑफ वेपन (एलआरएसओ) कहते हैं। यह स्टील्थ परमणु क्रूज मिसाइल है, जो दुश्मनों की पकड़ में नहीं आती। हाल ही में लोगों ने पहली बार असल में इसे उड़ते हुए देखा। कैलिफोर्निया के ऊपर परमाणु मिसाइल के परीक्षण के दौरान इसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई।

दूर से परमाणु हमले में यह है सक्षम

कैलिफोर्निया के ऊपर उड़ते बी-52एच बॉम्बर के पंख के नीचे लगे होने के दौरान, इसकी असली झलक पहली बार एक प्लेनस्पॉटर ने कैमरे में कैद कर ली। यह मिसाइल दुश्मन के रडार से बचने और बहुत लंबी दूरी से परमाणु हमला करने में सक्षम है। मिसाइल बी-52एच बॉम्बर के नीचे लगी हुई थी। विमान के दाहिने पंख के नीचे लगी मिसाइलें लगी हुई थीं।

विशेषताएं

- लंबाई- 6.4 मीटर (करीब 20 फीट)
- गति: सबसोनिक (850 किलोमीटर प्रति घंटा)
- दुनिया के सामने आई मिसाइल की तस्वीर
- 2030 के आसपास सेना में शामिल होगा
- दुश्मनों पर दूर से परमाणु हमला करने में सक्षम

- चौड़ाई 0.62 मीटर
- रेंज: 2500 किलोमीटर से ज्यादा
- वॉरहेड: परमाणु हथियार, हिरोशिमा के बम से 10 गुना शक्तिशाली बम गिराने की क्षमता
- वजन: 1360 किलोग्राम (करीब), अभी परीक्षण में है

सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल

ये मिसाइलें मल्टीपल इजेक्टर रैक के बाहरी स्टेशनों पर लगी हुई थीं, जो विमान के पंख के नीचे एक उपकरण है। इसमें एडवांस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। यह उड़ान के दौरान कई गोला-बारूद को रखता व छोड़ता है। मिसाइलों में एजीएम-181ए की पिछली तस्वीरों जैसी ही विशेषताएं दिखाई दीं, जिनमें मुड़ने वाले पंख, तीन सतहों वाली एक उलटी पूंछ और एक तीखे कोण वाला शरीर शामिल है।

पुरानी एयर क्रूज मिसाइल की जगह लेगी

विश्लेषकों का कहना है कि मिसाइल की विशेषताएं वायु सेना की नई परमाणु-सक्षम स्टैंडऑफ मिसाइल से काफी मिलती-जुलती हैं। इस मिसाइल को दूर से प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पुरानी एजीएम-86बी एयर-लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल की जगह लेगी। एलआरएसओ कई मायनों में एजीएम-86बी से अलग है। इसकी रेंज ज्यादा है, स्टील्थ बेहतर है, और मार्गदर्शन प्रणाली अपडेट की गई है। ये अपग्रेड इसे हवाई सुरक्षा को भेदकर दूर से हमला करने में सक्षम बनाते हैं।

रूस और चीन को जवाब

रक्षा विशेषज्ञ इसे रूस और चीन को जवाब के तौर पर देख रहे हैं। रूस ने हाल ही में परमाणु-संचालित क्रूज मिसाइल बुरेवेस्तनिक का परीक्षण किया है। यह मिसाइल सैद्धांतिक रूप से असीमित रेंज के लिए डिजाइन की गई है क्योंकि यह परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित है। बता दें कि चीन ने भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई है। इसका प्रदर्शन भी वह कर चुका है। यह बहुत बदलाव लाएगी।

अब तक रखा गया था गुप्त

बताया जाता है कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने अब तक एजीएम-181ए लॉन्ग रेंज स्टैंडऑफ वेपन (एलआरएसओ) की तैयारी को गुप्त रखा था। हालांकि, एजीएम-181ए मिसाइल के परीक्षण के दौरान इसकी तस्वीर दुनिया के सामने आ गई।

Hindustan Page No-15

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच ब्राजील में जुटे दुनियाभर के नेता

बेलेम (ब्राजील) एजेंसी। कई चुनौतियों के बीच जलवायु पर शिखर सम्मेलन सोमवार से ब्राजील के बेलेम शहर में शुरू हो रहा है। दुनियाभर के हजारों प्रतिनिधि इस सम्मेलन के लिए बेलेम में इकट्ठा हो चुके हैं। यह सम्मेलन तब हो रहा है जब वैश्विक तापमान ने नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं और चरम मौसम सहित जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभाव दुनियाभर में लोगों पर असर डाल रहे हैं।

कॉप क्या है?: कॉपी का मतलब है 'पार्टियों का सम्मेलन'। यह वार्षिक शिखर सम्मेलन उन देशों को एक साथ लाता है जिन्होंने 1992 की संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस

संधि का मुख्य उद्देश्य सभी देशों को मिलकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध करना है। यह संधि यह भी स्थापित करती है कि अमीर देशों की, जिन्होंने ग्रह-वार्मिंग उत्सर्जन में अधिक योगदान दिया है, समस्या को हल करने की जिम्मेदारी ज्यादा है। इस बार 30वां सम्मेलन हो रहा है इसलिए इसे कॉप-30 कहा जा रहा। पिछले कुछ वर्षों में, ये वार्षिक शिखर सम्मेलन भू-राजनीतिक और वित्तीय चर्चा का प्रमुख केंद्र बन गए हैं।

इस साल का कॉप-30 क्यों महत्वपूर्ण है?: कॉप का 30वां सम्मेलन बहुत खास है। 33 साल पहले ब्राजील में ही जलवायु संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। यह एक तरह से अपनी जड़ों की ओर लौटना है। ब्राजील चाहता है कि नए वादे करने के बजाय, देश पिछले वादों को पूरा करने पर ध्यान दें, जैसे कि कॉप28 में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को धीरे-धीरे खत्म करने का वादा। ब्राजील ने इसे अमेजन के वर्षावन शहर बेलेम में आयोजित करने का फैसला किया है।

Hindustan Page No-15

मुनीर को असीमित अधिकार देने के विधेयक पर पाक में विरोध तेज

आक्रोश

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाक सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को ताकतवर बनाने वाले 27वें संविधान संशोधन का विरोध शुरू हो गया है। एक तरफ सरकार संसद में संविधान संशोधन को पारित कराने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इसके खिलाफ रविवार को देशव्यापी प्रदर्शन ऐलान किया।

संविधान के अनुच्छेद 243 में परिवर्तन का प्रस्ताव है, जिसके तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीजेसीएससी) के पद को समाप्त कर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का नया पद सृजित किया जाना है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज रक्षा बलों का प्रमुख होगा। इसके जरिये पाक सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की ताकत और बढ़ जाएगी। इसके बाद मुनीर के पास न सिर्फ थल सेना, बल्कि वायु सेना और नौसेना का भी नियंत्रण होगा। विपक्ष इसका विरोध कर रही है। विपक्षी गठबंधन तहरीक-ए-तहाफुज आईन-ए-पाकिस्तान ने संशोधन के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन के प्रमुख अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, राष्ट्र को प्रस्तावित 27वें संशोधन के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ टीटीएपी का हिस्सा है।

पाक की संसदीय समिति ने संशोधन को मंजूरी दी

पाकिस्तान की संसद की संयुक्त संसदीय समितियों (सीनेट और नेशनल असेंबली) ने रविवार को विपक्ष के निशाने पर आए अनुच्छेद 243 में संशोधन को मंजूरी दे दी। जियो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह फैसला विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लिया गया, जिससे प्रस्तावित 27वें संविधान संशोधन की प्रक्रिया में एक अहम कदम पूरा हुआ। सूत्रों ने बताया कि समितियों ने मसौदे की अधिकांश धाराओं पर विचार-विमर्श पूरा कर लिया है, जिनमें अनुच्छेद 243 भी शामिल है। इसे मंजूरी दे दी गई।

राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी

सोमवार को मतदान होने पर उसे कम से कम 64 सीनेटर का दो-तिहाई बहुमत मिल जाएगा। सीनेट के बाद इसे नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा, जहां इसे फिर से दो-तिहाई बहुमत से पारित होना होगा। अंतिम चरण में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी जरूरी होगी।

"अजरबैजान से लौटने पर मुझे पता चला कि हमारी पार्टी के कुछ सीनेटरों ने प्रधानमंत्री को छूट संबंधी एक संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं उनकी मंशा को स्वीकार करता हूं। – शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री, पाकिस्तान

27वें संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधान

1 सशस्त्र बलों के प्रमुख के रूप में नया पद सृजित किया जाएगा

27 नवंबर 2025 से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का नया पद बनाया जाएगा, जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च प्रमुख होगा।

2 वर्तमान सेना प्रमुख का पदोन्नयन

चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की भूमिका संभालने का अधिकार दिया जाएगा। इससे आगे व्यापक बदलाव आएगा।

3 मानद सैन्य उपाधियां आजीवन मान्य रहेंगी

फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट जैसी उपाधियां आजीवन बनी रहेंगी।

4 नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की नियुक्ति प्रक्रिया

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर सेना से नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांडर की नियुक्ति करेंगे।

5 न्यायिक नियुक्तियों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

अब पाक सेना प्रमुख हो सकते हैं सबसे ताकतवर

इस्लामाबाद, एजेंसी। सीनेट में पेश किए गए पाकिस्तान के प्रस्तावित 27वें संविधान संशोधन विधेयक ने कानूनी विशेषज्ञों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों के बीच बहस छेड़ दी है। आलोचकों का कहना है यह बिल देश के न्यायिक ढांचे में पूरी तरह परिवर्तन ला सकता है।

विधेयक क्या है : यह पाकिस्तान के संविधान में एक बड़ा बदलाव लाने वाला प्रस्तावित कानून है। सरकार इसे न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए लाई है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति छीन लेगा। सूत्रों के मुताबिक, एक नया शीर्ष कोर्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम है संघीय संवैधानिक न्यायालय। यह नया न्यायालय अब वे महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों को देखेगा, जो अब तक केवल सर्वोच्च न्यायालय देखता था। इससे शीर्ष कोर्ट की शक्ति कम होगी। यह बिल पास हुआ तो सेना प्रमुख मुनीर आजीवन फील्ड मार्शल के पद पर रहेंगे।

Hindustan Page No-15

कॉप-30

आज (10 नवंबर) जब यूनेस्को की पहल पर टिकाऊ भविष्य के निर्माण में विज्ञान के महत्व को समझते हुए 'शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस' मनाया जा रहा है, तब ब्राजील के बेलेम में 197 देशों के प्रतिनिधि इस बात पर चर्चा करने के लिए जुटे हैं कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से कैसे निपटा जाए? यह मूलतः उन देशों की सालाना बैठक है, जो जलवायु परिवर्तन पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर सहमत हैं। हालांकि, यह उनका 30वां सम्मेलन (कॉप-30) है और प्रतिनिधियों का जमावड़ा बीते गुरुवार से ही होने लगा था, पर इसकी आधिकारिक शुरुआत आज से हो रही है, जो 21 नवंबर तक चलेगी। यह बैठक कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी से होता है कि गुरुवार को ही विश्व मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी रिपोर्ट में साल 2025 को अब तक के ज्ञात इतिहास का दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहने का अंदेशा जताया है। इससे पहले साल 2023 और 2024 में भी वैश्विक गर्मी के रिकॉर्ड टूट चुके हैं और चरम मौसम के नए मापदंड बन चुके हैं। साफ है, बदलती आबोहवा अब मानव अस्तित्व को चुनौती देने लगी है।

ऐसे में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस की तल्खी समझी जा सकती है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने सख्त लफ्जों में कहा कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखने में हम सफल नहीं रहे हैं, जो हमारी नैतिक विफलता और लापरवाही है। हालांकि, चुनौती सिर्फ बढ़ता तापमान नहीं है। पूरी दुनिया में ऊर्जा की मांग अनवरत बढ़ रही है और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपनी जलवायु नीतियों को बदलने लगी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में सत्ता संभालते ही उस ऐतिहासिक पेरिस समझौते से खुद को अलग करने का एलान कर दिया, जिसे वैश्विक तापमान वृद्धि को धीमा करने के इरादे से 2015 में काफी मशक्कत के बाद स्वीकार किया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा दे रहे हैं और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता से मुंह मोड़ रहे हैं। हालांकि, संतोष की बात यह है कि सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश चीन अक्षय ऊर्जा में अपना निवेश बढ़ा रहा है और भारत ने भी हरित ऊर्जा को लेकर अपनी गति तेज कर दी है। अक्तूबर के आखिरी दिनों में हमारी कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट से अधिक हो गई, जिसमें आधा से अधिक, यानी 256 गीगावाट ऊर्जा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से मिलने लगी है। यह स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

अब तमाम नेताओं को सहमति बनानी ही होगी। खास तौर से तब, जब उत्सर्जन पिछले साल एक और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया हो।

कॉप-29 में ऐसे आर्थिक पैकेज पर जोर दिया गया था, जिससे उत्सर्जन में कमी करने से विकासशील देशों को होने वाले नुकसान की भरपायी की जा हो। हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद संपन्न देश सालाना 300 अरब डॉलर की सहायता-राशि देने पर ही राजी हुए थे, जिसे भारत सहित कई देशों ने खारिज कर दिया था, क्योंकि मांग साल 2035 तक हर वर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर की रही है। जाहिर है, इस बार भी यह मुद्दा सुर्खियों में रहेगा। साथ ही, तमाम देशों को अपने यहां उत्सर्जन कम करने और लक्ष्य के अनुकूल कदम बढ़ाने का 'रोडमैप' पेश करना होगा। बेशक, यह आसान काम नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पर विकसित और विकासशील देशों के बीच गहरे मतभेद रहे हैं, पर तमाम नेताओं को इस पर सहमति बनानी ही होगी। खास तौर से तब, जब उत्सर्जन पिछले साल एक और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया हो।

Hindustan Page No-10

नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण पर भारत का फोकस

जयप्रकाश रंजन ● जागरण

● सोलर पैनल, विंड टर्बाइन ब्लेड्स और संबंधित उपकरण निर्माण के लिए पहले से घोषित प्रोत्साहन नीति में और सुधार करेगी सरकार

नई दिल्ली: सौर, पवन समेत सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बनने वाली बिजली में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने के बाद भारत ने अब इन उद्योगों से जुड़े उपकरणों के निर्माण पर फोकस किया है। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने सोलर पैनल, विंड टर्बाइन ब्लेड्स और संबंधित उपकरणों के घरेलू निर्माण को तेज करने के लिए पहले से घोषित प्रोत्साहन नीति में और सुधार करने का फैसला किया है। इसके तहत 2030 तक वैश्विक विंड ऊर्जा बाजार में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले तीन-चार वर्षों में सोलर पैनल निर्माण में अच्छी उपलब्धि के बाद अमेरिका, यूरोपीय व दक्षिणी अमेरिकी बाजार के लिए नई महत्वाकांक्षी योजना तैयार की जा रही है। सरकार की नई पहल आयात निर्भरता घटाने के साथ ही गैर-जीवाश्म आधारित ईंधन क्षमता में देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद देगी।

भारत की यह योजना दुनिया में सोलर व विंड ऊर्जा बाजार में उपलब्ध अवसरों को देखते हुए तैयार की गई है। अभी इस बाजार पर चीन का कब्जा है, जबकि यूरोपीय व अमेरिका में होने वाला निर्माण काफी महंगा है। विकसित देश एक तरफ चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ विकासशील देशों की तरफ से वैकल्पिक बाजार खोजे रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार को विकासशील देशों में काफी संभावनाएं दिख रही हैं। उदाहरण के तौर पर- वैश्विक सोलर ऊर्जा बाजार का आकार 2024 में लगभग 271.73 अरब डालर था, जिसके 2034 तक 1,090.78 अरब डालर पर पहुंचने का अनुमान है।

वर्ष 2024 में भारत ने सिर्फ दो अरब डालर के सोलर पीवी माड्यूल का निर्यात किया था। वैसे यह वर्ष 2022 के मुकाबले 23 गुना अधिक है, लेकिन चीन के निर्यात 60 अरब डालर के सामने कुछ नहीं है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि सोलर पैनल निर्माता भारतीय कंपनियों ने अमेरिकी बाजार में पैठ बना रही है।

अब पवन ऊर्जा से जुड़े उपकरणों की बात करें तो अभी यह बाजार तकरीबन 100 अरब डालर का है जिसके वर्ष 2030 तक 142 अरब डालर पर पहुंचने की बात कही जा रही है। एमएनआरई ने कहा है कि वह इसका 10 प्रतिशत बाजार हासिल करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगी। मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि चीन की नंबर वन स्थिति भारत के लिए चुनौती और अवसर दोनों है। 2024-2025 में वैश्विक सोलर माड्यूल उत्पादन में चीन का हिस्सा 92 प्रतिशत और विंड टर्बाइन में 82 प्रतिशत था।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

Dainik Jagaran Page No-13

वित्तीय स्थिति बदहाल

कैसे बनेंगे स्कूल-अस्पताल

राज्य अपने बजट का करीब 70 प्रतिशत वेतन, पेंशन, सब्सिडी और कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च कर रहे हैं। सिर्फ 30 प्रतिशत बजट ही बाकी खर्च के लिए बचता है। हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि राज्यों में विकास परियोजनाओं के लिए कम संसाधन का आवंटन होने से देश की आर्थिक वृद्धि दर पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। कुछ राज्यों की वित्तीय व्यवस्था तो इस हद तक चरमरा गई है कि उनको नियमित काम-काज के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। वहीं, वर्तमान समय की जरूरत है कि बढ़ती आबादी के साथ उसी अनुपात में स्कूल, अस्पताल और दूसरी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएं जिससे नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए जरूरी सुविधाएं आसानी से हासिल कर सकें और जीवनस्तर बेहतर बना सकें। लेकिन जमीन पर इसका ठीक उलटा होता हुआ दिख रहा है। राज्य डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पर अधिक जोर दे रहे हैं। सत्तारूढ़ दलों को चुनाव में इसका फायदा भी मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि कैश ट्रांसफर किस कीमत पर हो रहा है? क्या आम लोगों को स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक परिवहन और दूसरी सुविधाओं की जरूरत नहीं है और अगर राज्यों के पास इनके लिए पैसे नहीं हैं तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। इसी सवाल पर केंद्रित है आज का मुद्दा...

शीर्ष 10 राज्यों का प्रतिबद्ध खर्च (राजस्व का %)

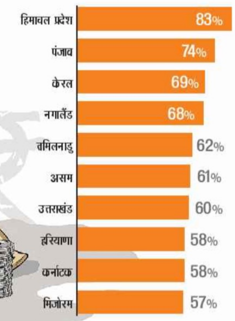

बजट अनुमान 2025-26

सब्सिडी पर राजस्व का 10 प्रतिशत से अधिक खर्च कर रहे हैं नौ राज्य

(सब्सिडी पर खर्च प्रतिशत में)
बजट अनुमान 2025-26

सात राज्यों का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3 प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान

(बजट 2025-26)

13 राज्यों की देनदारी एसजीडीपी का 30 प्रतिशत से अधिक, मार्च 2025 अनुमानित

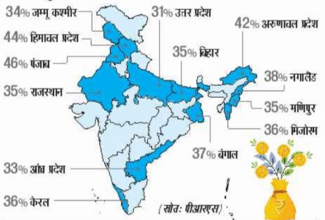

(स्रोत: पीआरएस)

राज्यों पर औसत कर्ज जीएसडीपी का 27.2 प्रतिशत

एफआरबीएम समीक्षा समिति ने डेट टू जीडीपी रेशियो की सीमा केंद्र के लिए 40 प्रतिशत और राज्यों के लिए 20 निर्धारित की थी। इस लक्ष्य को 2023 तक हासिल किया जाना था। 2024-25 में, राज्यों की औसत अनुमानित उधारी जीएसडीपी का 27.2 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि राज्य कर्ज की तय सीमा को पहले ही पार कर चुके हैं। राज्यों में चुनावी फायदे के लिए मुफ्त सुविधाएं देने की होड़ को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह आंकड़ा और बढ़ने वाला है।

जागरण रिसर्च

राज्यों में महिलाओं को कैश ट्रांसफर

राज्य	स्कीम का नाम	कैश ट्रांसफर प्रतिमाह (रुपये में)	बजट प्रविधान (2025-26 बजट अनुमान) (करोड़ रुपये में)
असम	ओरुनोदोई योजना	1,250	500
छत्तीसगढ़	महतारी वंदन योजना	1,000	5,500
दिल्ली	महिला समृद्धि योजना	2,500	5,110
हिमाचल प्रदेश	इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना	1,500	138
हरियाणा	लाडो लक्ष्मी योजना	2,100	5,000
झारखंड	सीएम मैय्या सम्मान योजना	2,500	13,363
कर्नाटक	गृह लक्ष्मी योजना	2,000	28,608
महाराष्ट्र	मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहना योजना	1,500	36,000
मध्य प्रदेश	मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना	1,250	18,669
ओडिशा	सुभद्रा योजना	833	10,145
तमिलनाडु	मगलिर उरीमाई थोगाई	1,000	13,807
बंगाल	लक्ष्मीर भंडार योजना	1,000-1,200	26,700

60% है भारत के कुल सार्वजनिक व्यय में राज्यों की हिस्सेदारी

40% तय की गई है केंद्र के लिए डेट टू जीडीपी रेशियो की सीमा

20% से अधिक नहीं होना चाहिए राज्यों का कर्ज जीएसडीपी का

Dainik Jagaran Page No-11

प्रमोद, कृष्णा व सुकांत ने लगाई पदकों की झड़ी

शिजुओका सिटी (जापान), प्रेट्र: स्टार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और सुकांत कदम ने रविवार को जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे भारत ने आधे दर्जन से अधिक स्वर्ण पदक जीते। भगत ने सिंगल्स, डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक जीता, जबकि टोक्यो पैरालिंपिक चैंपियन नागर ने सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक हासिल किए। सुकांत ने पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीतने के अलावा सिंगल्स में रजत पदक हासिल किया। भगत ने एसएल3 वर्ग में पुरुष सिंगल्स में जापान के दाइसुके फुजिहारा के विरुद्ध पहला गेम गंवाने और दूसरे में

पदकों के साथ भारतीय पैरा शटलर

16-19 से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए एक घंटे और 33 मिनट में 17-21, 21-19, 21-10 से जीत दर्ज की। पुरुष डबल्स में भगत ने सुकांत के साथ मिलकर जगदीश दिल्ली और नवीन शिवकुमार की हमवतन जोड़ी को 21-17, 18-21, 21-16 से हराया।

Useful For Mains

देश में समावेशी विकास होगा बाधित

विकास सिंह
विशेषज्ञ, समग्र विकास

पूंजीगत खर्च ही समावेशी विकास की प्रक्रिया को तेज करता है। विकास के लिए राज्यों के पास कम संसाधन बचने से पूंजी निर्माण की प्रक्रिया रुक जाएगी। लोकलुभावन योजनाओं पर जमकर खर्च करने की कीमत भविष्य में संसाधनों के संकट के तौर पर चुकानी पड़ेगी।

भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत के आसपास बनी हुई है और विदेशी निवेशक इसे निवेश के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि मजबूत आर्थिक संकेतकों के बीच विकास के मोर्चे पर एक गहरा असंतुलन छिपा हुआ है। सबको बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए समावेशी विकास की धारा पूरे प्रवाह के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसका कारण महत्वाकांक्षा का अभाव नहीं गलत प्राथमिकताएं हैं। भारत के राज्य विकास की वास्तविक प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन इन्हीं राज्यों ने खुद को एक खतरनाक पैटर्न में फंसा लिया है। ये राज्य चुनावी फायदे के लिए संसाधनों को अनाप शनाप तरीके से खर्च कर रहे हैं। इससे पूंजीगत खर्च के लिए बहुत कम पैसा बचता है। पूंजीगत खर्च ही पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को तेज करता है और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को बढ़ाता है। ऐसे में ग्रोथ का इंजन एक ही पहिये पर घिसट रहा है। भारत में वित्तीय असंतुलन केंद्र से नहीं बल्कि राज्यों से शुरू होता है। लोकलुभावन कदम जैसे कर्ज माफी, मुफ्त बिजली और कैश ट्रांसफर आज कल चुनावी मौसम का अभिन्न हिस्सा हो गया है। पंजाब ने 2024-25 में अपनी राजस्व प्राप्तियों का करीब 76 प्रतिशत वेतन, पेंशन और कर्ज का ब्याज चुकाने पर खर्च किया। ऐसे में विकास के लिए बहुत कम पैसा गया। हिमाचल ने 2025-26 के बजट का करीब 60-65 प्रतिशत इसी मद के लिए आवंटित किया है। यह एक खराब ट्रेंड है, जहां राज्य कल की क्षमता की कीमत पर आज खर्च कर रहे हैं। पूंजीगत खर्च समावेशी विकास का आधार है। यह सड़कों, स्कूलों और कारखानों के लिए पैसा मुहैया कराता है जिससे रोजगार पैदा होता है। इसके बावजूद बहुत से राज्यों में पूंजीगत खर्च लोकलुभावनवाद का पहला शिकार बन गया है। 2024-25 में पंजाब का पूंजीगत खर्च 7,445 करोड़ रुपये रहा। जो प्रमुख राज्यों में सबसे कम है और वेतन व ब्याज पर होने वाले खर्च के दसवें हिस्से से भी कम है। हिमाचल प्रदेश का पूंजीगत खर्च लगभग 6,270 करोड़ रुपये है। बिहार में, प्रति व्यक्ति आय मात्र 66,828 रुपये है, जो भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,15,935 का बमुश्किल एक तिहाई है। हालांकि बिहार ने अपने निवेश अनुपात में सुधार किया है, पूंजीगत व्यय अभी भी कुल व्यय का लगभग 10-12 प्रतिशत ही है। कुल मिलाकर, भारत के सार्वजनिक व्यय में राज्यों की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है। राज्यों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, मुफ्त सौगातों की घोषणाएं बढ़ती जाती हैं। मुफ्त बिजली, पेंशन और ''गारंटी'' अब राजकोषीय परिदृश्य पर हावी हो गए हैं। यह और कुछ नहीं, उधार के पैसों से उदारता की होड़ है। पंजाब का कर्ज अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के लगभग 46 प्रतिशत के बराबर है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश का कर्ज वेतन संशोधन, बिजली सब्सिडी और पेंशन देनदारियों के कारण जीएसडीपी के 44 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है। दोनों ही राज्यों में ब्याज भुगतान पूंजीगत खर्च से अधिक है।

विडंबना यह है कि जो राज्य समावेशन की सबसे ज्यादा दुहाई देते हैं, वही अपने भविष्य को सबसे ज्यादा लापरवाही से गिरवी रख रहे हैं। नेकनीयत से किया गया कल्याणकारी कार्यक्रम भी, अगर गलत तरीके से लक्षित किया जाए, तो प्रतिगामी हो सकता है। जब अमीर और मध्यम वर्ग सब्सिडी से समान रूप से लाभान्वित होते हैं, तो सामाजिक व्यय राजकोषीय रिसाव में बदल जाता है।

अगर वित्तीय प्रबंधन में सुधार नहीं किया गया तो भारत के राज्यों का हाल भी लैटिन अमेरिकी देशों जैसा हो सकता है। इन देशों में राज्यों ने लोगों को जनकल्याण के नाम पर मुफ्त की सुविधाओं पर खूब खर्च किया और अब संसाधनों के संकट का सामना कर रहे हैं ।

ब्राजील के राज्यों ने पूंजीगत खर्च में कटौती की, जिससे कर्ज सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 40 प्रतिशत से अधिक हो गया और विकास दर लगभग शून्य हो गई। भारत के राज्य पंजाब, बंगाल और हिमाचल प्रदेश भी इसी राह पर हैं। 16वें वित्त आयोग को पूंजीगत खर्च के लक्ष्यों के साथ विकेंद्रीकरण को जोड़ना चाहिए। कनाडा प्रांतीय स्तर पर बुनियादी ढांचे के लिए अनुदानों के साथ ऐसा ही करता है। राज्यों को केरल के राजस्व-समर्थित केआइआइएफडी माडल को अपनाना चाहिए। इसका मतलब है बजट से बाहर उधार लें, लेकिन केवल भविष्य के करों के विरुद्ध। कल्याणकारी योजनाएं समयबद्ध, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर से जुड़ी और नौकरियों से प्रेरित होनी चाहिए। ऐसे सुरक्षा उपायों के बिना, भारत की 7 प्रतिशत की वृद्धि दर बढ़ते संघीय विभाजन को छिपा देगी। एक राज्य राजमार्ग बनाएगा और दूसरा राज्य अपने संसाधनों को सब्सिडी पर खर्च करेगा।

Dainik Jagaran Page No-11

पूंजीगत खर्च के लिए पैसों का संकट

गौरव वल्लभ
पीटी सदस्य, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

राज्य अपने राजस्व प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी पर खर्च कर रहे हैं। इससे उनके पास पूंजीगत खर्च के लिए पैसा ही नहीं बच रहा है। पूंजीगत खर्च कम होने से निजी निवेश भी घट जाता है। ऐसे में विकास की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है।

वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों ने अपनी राजस्व प्राप्तियों का लगभग 53 प्रतिशत वेतन और पेंशन पर खर्च किया और करीब 9 प्रतिशत सब्सिडी पर खर्च किया। यह देश के सभी राज्यों का औसत खर्च है। इस तरह से राज्यों की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 62 प्रतिशत पहले प्रतिबद्ध खर्च के लिए फिक्स हो जाता है। बिना एक भी स्कूल कालेज और सड़कें बने हुए। वहीं, कई राज्य जैसे पंजाब है, वहां राजस्व प्राप्तियों का 107 प्रतिशत प्रतिबद्ध खर्च में चला जाता है।

इसका मतलब है कि पंजाब का वेतन, पेंशन ब्याज और सब्सिडी पर खर्च कुल राजस्व प्राप्तियों से भी अधिक हो गया और इसके लिए भी राज्य को कर्ज लेना पड़ता है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश वेतन, पेंशन ब्याज और सब्सिडी में राजस्व प्राप्तियों का करीब 85 प्रतिशत खर्च कर रहा है। तमिलनाडु इन मदों पर 77 प्रतिशत और केरल 75 प्रतिशत खर्च कर रहा है। इस तरह से कई राज्यों के पास बुनियादी सुविधाएं देने के लिए कोई पैसा ही नहीं बचता है। एक तरह से पैसा आता और वेतन, पेंशन ब्याज और सब्सिडी पर उनका पैसा चला जाता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर राज्य पूंजीगत खर्च के मद में जैसे सड़कें बनाने पर एक रुपये खर्च करता है तो उसे इसका इकोनमिक आउटपुट 2.5 से 3 रुपया मिलता है। लेकिन पूंजीगत मद में खर्च करने के लिए राज्यों के पास पैसा ही नहीं है और जिन मदों में हम अभी खर्च कर रहे हैं वहां एक रुपया खर्च करने पर इकोनमिक आउटपुट एक रुपया ही मिलता है। इसका मतलब है कि इन मदों में खर्च से कोई पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है। पूंजीगत खर्च से इकोनमिक आउटपुट में वैल्यू एडीशन होता है और इसके लिए राज्यों के पास पैसा ही नहीं बचता है। इसका प्रमुख कारण है वेतन और पेंशन। राज्यों का वेतन और पेंशन पर औसत खर्च राजस्व प्राप्तियों का करीब 35-40 प्रतिशत है। सब्सिडी पर खर्च लगभग नौ प्रतिशत है। इससे निजात पाने के लिए दो तीन सुझाव हैं। पहला है बिजली पर खर्च। कई राज्यों में बिजली वितरण में नुकसान 25 से 30 प्रतिशत है। इस नुकसान की भरपाई राजस्व से ही होता है। अगर राज्य इस नुकसान को खत्म करने पर काम करें तो राजस्व प्राप्तियों का 5-10 प्रतिशत इसी से बच सकता है। दूसरा, सबको सब्सिडी देने का मसला है। जैसे राज्य कह देते हैं सभी नागरिकों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त। यह सब्सिडी सभी नागरिकों के बजाए सिर्फ उन्हीं लोगों या समूहों को मिलनी चाहिए जिनको इसकी वास्तव में जरूरत है या जो लोग आर्थिक तौर पर इसे वहन करने में सक्षम नहीं हैं। तीसरा मसला है पेंशन का। राज्यों को चुनाव से प्रभावित होकर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बजाय यूनीफाइड पेंशन स्कीम को लागू करना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम आर्थिक तौर पर वहनीय नहीं है। जिन राज्यों ने अपना पूंजीगत खर्च जीडीपी के तीन प्रतिशत के आसपास रखा, जैसे उत्तर प्रदेश, गुजराज और तेलंगाना, उनको इसका फायदा इस रूप में मिला कि जब पूंजीगत खर्च बढ़ता है तो निजी निवेश भी आता है। इससे जीएसटी संग्रह भी बढ़ता है। जब पूंजीगत खर्च कम होता है तो निजी निवेश भी घट जाता है। इसके अलावा राज्यों को प्रोजेक्ट लागू करने की क्षमता में भी सुधार करने की जरूरत है।

बेहतर भविष्य की आस में बिहार

रामानंद शर्मा

> बिहार में आज प्रमुख चुनौती उस अविश्वास को दूर करना है, जो दशकों के अधूरे आश्वासनों से उपजा है

बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन राज्य को औद्योगिक केंद्र में बदलने का स्वप्न दिखा रहा है, तो विपक्षी महागठबंधन सामाजिक न्याय और आरक्षण के अपने आजमाए हुए मुद्दों को नई धार देता दिख रहा है। किंतु इसके बीच कुछ बुनियादी प्रश्न हैं, जो बिहार के आत्मा को कुरेद रहे हैं। क्या यह चुनाव केवल सत्ता के अंकगणित का एक और अध्याय बनकर रह जाएगा या यह उस गहरी खाई को पाटने का एक ईमानदार अवसर बनेगा, जो वादों और यथार्थ के बीच दशकों से चौड़ी होती जा रही है? यह केवल व्यक्तित्वों या गठबंधनों की प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि उस समाज के लिए सामूहिक आत्म-चिंतन का एक दुर्लभ क्षण है, जो अपनी गौरवशाली सभ्यतागत विरासत और अपनी वर्तमान वास्तविकता के बीच की असहनीय दूरी से जूझ रहा है।

आज बिहार की धरती प्रवासन, बेरोजगारी और अधूरी आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि क्या बिहार की राजनीति नवीनीकरण का एक शक्तिशाली साधन बन सकती है? बिहार की राजनीति में आज किसी भी दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती नए वादे गढ़ना नहीं, बल्कि उस गहरे अविश्वास और संदेह को दूर करना है, जो दशकों के अधूरे आश्वासनों से उपजा है। हर चुनावी चक्र 'अधूरी उम्मीदों की बढ़ती भावना' को ही मजबूत करता है। संकट अब उम्मीद का नहीं, विश्वसनीयता का है, जहां नागरिक अब केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि अपनी आंखों के सामने परिवर्तन का ठोस प्रमाण मांग रहे हैं। बिहार अपनी युवा पीढ़ी को लगातार विफल कर रहा है, जिससे एक ऐसा जनसांख्यिकीय संकट पैदा हो रहा है, जिसकी विशेषता चौंकाने वाली बेरोजगारी, मजबूरन प्रवासन और व्यवस्थागत निराशा है। राज्य की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है, लेकिन इससे भी भयावह यह है कि यहां के अधिकांश युवाओं ने काम खोजने की उम्मीद ही छोड़ दी है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे युवाओं में है। स्नातकों के लिए यह 14.7 प्रतिशत और स्नातकोत्तर के लिए 19 प्रतिशत तक पहुंच गई है। पटना की सड़कों पर गूंजता नारा, "करो तो सरकारी नौकरी, नहीं तो बेचो तरकारी" लाखों युवाओं के टूटे सपनों का प्रतीक बन गया है। इसी निराशा का सीधा परिणाम प्रवासन है।

पहले चरण में मतदान के लिए कतार में मतदाता ● फाइल

जब राज्य में अवसर नहीं मिलते, तो लगभग लाखों बिहारी श्रमिक दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्थाओं को अपने खून-पसीने से सींचते हैं। बार-बार होने वाले परीक्षा पेपर लीक जैसी व्यवस्थागत विफलताएं युवाओं की आकांक्षाओं पर प्रणालीगत हिंसा के समान हैं। जो भूमि कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे ज्ञान के वैश्विक केंद्रों का घर थी, वह आज अपने बच्चों को मूलभूत शिक्षा प्रदान करने में भी विफल हो रही है, जिससे गरीबी और प्रवासन का एक अंतहीन चक्र बना हुआ है। गणतंत्र के शुरुआती दिनों में जहां देश के विश्वविद्यालय नामांकन में बिहार का लगभग दसवां हिस्सा था, वहीं आज यह तीन प्रतिशत से भी कम रह गया है। स्कूल मौजूद हैं, शिक्षक नियुक्त हैं, पाठ्यक्रम छपे हुए हैं, लेकिन सीखने-सिखाने की जवाबदेही नदारद है। जिनके पास साधन हैं, वे अपने बच्चों को राज्य से बाहर भेजकर इस व्यवस्था से बच निकलते हैं, जबकि गरीब एक ऐसी प्रणाली में फंस गए हैं, जो ऊपर उठने का कोई वास्तविक रास्ता नहीं दिखाती है। जब तक ज्ञान की नींव ही कमजोर हो, तब तक कौशल विकास और उद्योगीकरण की बातें बेमानी लगती हैं। किसी भी सरकार के लिए सार्वजनिक शिक्षा का पुनर्निर्माण सबसे परिवर्तनकारी कार्य हो सकता है, फिर भी यह राजनीतिक घोषणापत्रों में प्राथमिकता की दृष्टि से एकदम निचले पायदान पर है।

वर्ष 2016 में लागू की गई शराबबंदी आज इस बात का उदाहरण बन गई है कि कैसे नेक इरादों वाली नीतियां जब खराब तरीके से डिजाइन और लागू की जाती हैं, तो प्रशासनिक आपदाओं में बदल सकती हैं। शराब खत्म होने के बजाय इस प्रतिबंध ने एक समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है, जिसने शराब तस्करों, पुलिस और राजनेताओं के एक नए गठजोड़ का जाल बुना है। जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें इस काले बाजार का क्रूर परिणाम हैं। इसने अदालतों को मामलों से और जेलों को छोटे-मोटे अपराधियों से भर दिया है। मार्च 2025 तक 9,36,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए और 14.3 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि द लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन का अनुमान है कि इस प्रतिबंध ने राज्य में घरेलू हिंसा के 21 लाख मामलों को रोका है। सामाजिक दृष्टि से यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है और बताता है कि अभी भी अधिकतर महिलाएं इस नीति का समर्थन क्यों करती हैं। पुराने स्थापित दल इस मुद्दे पर फंसे हुए हैं। वे न तो इसकी विफलताओं को स्वीकार कर सकते हैं और न ही इसे निरस्त करने का प्रस्ताव देकर एक प्रमुख वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम उठा सकते हैं। सवाल केवल अगले पांच साल के शासन का नहीं, बल्कि यह है कि बिहार कैसा शासन स्वीकार करने को तैयार है। यदि मतदाता जनता के प्रति जवाबदेह शासन के निर्माण में भागीदार बनते हैं, तो वे राजनीति को नवीनीकरण का एक साधन बनने के लिए बाध्य कर सकते हैं।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट कालेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

फिर से न छिड़े परमाणु हथियारों की होड़

शिवकांत शर्मा

परमाणु परीक्षण शुरू करने का ट्रंप का एलान भारत जैसी उभरती हुई शक्तियों के लिए सिरदर्द ही बनेगा

भारत में तो एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बातें ही होती हैं, लेकिन असली बम तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात से पहले ही फोड़ दिया। उन्होंने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर लिखा, 'चूंकि कई दूसरे देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने युद्ध विभाग को भी तत्काल दूसरे देशों के स्तर के परमाणु परीक्षण शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं।' परीक्षण करने वाले देशों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने सीबीएस न्यूज को दिए साक्षात्कार में रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तान का नाम भी लिया। नवंबर 1996 में पारित हुई परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी के तहत नागरिक या सैनिक किसी भी उद्देश्य से परमाणु परीक्षण करना प्रतिबंधित है। हालांकि इस संधि का अमेरिका ने अभी तक अनुमोदन नहीं किया है, लेकिन वही इसका सबसे प्रबल प्रायोजक-पैरोकार रहा है। इसलिए ट्रंप के एलान से परमाणु परीक्षण निरीक्षकों, निरस्त्रीकरण विशेषज्ञों और दूसरी परमाणु शक्तियों में हैरत और परेशानी की लहर दौड़ना स्वाभाविक था। ट्रंप ने जिन चार देशों पर छिपकर परीक्षण करने के आरोप लगाए उनमें से उत्तर कोरिया ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर चीन और रूस ने ट्रंप के आरोपों का खंडन करते हुए परमाणु परीक्षण प्रतिबंध का पालन करने के दावे किए। और तो और पाकिस्तान ने भी खंडन करने में ढिलाई नहीं दिखाई। पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 'पाकिस्तान 1998 के बाद से परीक्षणों पर लगाए स्वैच्छिक विराम का पालन कर रहा है। पाकिस्तान ने न तो परमाणु परीक्षण करने में पहल की थी और न वह उन्हें दोबारा शुरू करने में पहल करेगा।'

पाकिस्तान के परमाणु अप्रसार के अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए परमाणु बम बनाने और उसकी तकनीक ईरान, लीबिया और उत्तरी कोरिया जैसे देशों को बेचने के विवादास्पद इतिहास को देखते हुए उसकी इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता कि वह परीक्षणों पर लगे प्रतिबंध का स्वेच्छा से पालन कर रहा है। परमाणु अस्त्रों के प्रयोग में पहल न करने की भारत की नीति के विपरीत पहले प्रयोग करने की नीति पर चलना और तरह-तरह के परमाणु बमों के प्रयोग की धमकी देते रहना भी पाकिस्तान की नीयत पर संदेह पैदा करता है। फिर भी, परमाणु परीक्षणों पर निगाह रखने के लिए बनी सीटीबीटी संगठन की अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण प्रणाली आइएमएस ने अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी है कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है। रूस ने आखिरी परमाणु परीक्षण सोवियत संघ के विखंडन से एक साल पहले 1991 में किया था और चीन ने 1996 में। उसके बाद इस सदी में उत्तर कोरिया को छोड़कर किसी देश ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है।

ट्रंप ने रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान पर लगाया परमाणु परीक्षण करने का आरोप • फाइल

ट्रंप का एलान कई सवाल खड़े करता है। मसलन क्या रूस, चीन और पाकिस्तान वाकई ऐसे परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जिनकी भनक आइएमएस को भी नहीं है? यदि ऐसा है तो फिर उसकी उपादेयता क्या है? अमेरिका के परमाणु परीक्षण शुरू करने से विश्व में परमाणु अस्त्रों की जो होड़ शुरू होगी उसे कैसे रोका जा सकेगा? इनका स्पष्टीकरण देने का काम ट्रंप ने अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को सौंपा। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने जिन परमाणु परीक्षणों को शुरू करने का एलान किया है वे सब-क्रिटिकल या ठंडे परमाणु परीक्षण हैं जिनसे रेडियोधर्मिता नहीं फैलती।' राइट का उद्देश्य दुनिया की चिंता दूर करने से अधिक अमेरिकी राज्य नेवाडा के निवासियों की चिंता दूर करना था, जो अमेरिका के परमाणु परीक्षण स्थल के पास रहते हैं। यहां पर 1992 के बाद से कोई परमाणु परीक्षण नहीं हुआ है और अब लोग परीक्षणों का कड़ा विरोध करते हैं।

हालांकि ट्रंप ने स्वयं इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वे विस्फोट वाले परीक्षण की नहीं, बल्कि सब-क्रिटिकल यानी ठंडे प्रायोगिक परीक्षण की बात कर रहे थे। बात से पलट जाना और मंत्रियों की बात काट देना उनके लिए आम बात है। इसलिए वे क्या कहना चाहते थे और क्यों, यह वही बता सकते हैं। फिर भी, यदि क्रिस राइट की बात सही मान ली जाए तब भी यह समझ नहीं आता कि इसके लिए सार्वजनिक एलान करने की क्या जरूरत थी और वह भी चीनी राष्ट्रपति के साथ होने वाली मुलाकात से ठीक पहले। कंप्यूटरों पर और प्रयोगशालाओं में आभासी ठंडे परीक्षणों का अमेरिका के पास सबसे पुराना अनुभव और तकनीकी दक्षता है। आजकल उसी के सहारे परमाणु अस्त्रों का विकास और नवीनीकरण किया जाता है। अमेरिका, रूस और चीन के पास कुल मिलाकर 12 हजार के लगभग परमाणु बम हैं जिनसे दुनिया को कई बार ध्वस्त किया जा सकता है। इसलिए अब दौड़ परमाणु बम बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें शत्रु के रक्षा कवच को भेद कर लक्ष्य तक पहुंचाने वाले प्रक्षेपास्त्रों के विकास की है, जिसमें रूस और चीन दोनों लगे हैं।

कुछ रणनीतिकारों का मानना है कि परीक्षण शुरू करने का एलान भभकी देकर सौदा पटाने की ट्रंप की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति से हुई मुलाकात से कुछ ही दिन पहले रूस ने पोसाइडन परमाणु तारपीडो और बुरेवेस्तनिक परमाणु क्रूज मिसाइल के परीक्षण किए थे और दावा किया था कि ये दोनों अमेरिका के रक्षा कवच को भेदकर परमाणु बमों से लक्ष्य पर वार कर सकते हैं। इसलिए शायद ट्रंप परमाणु परीक्षण शुरू करने का नाटकीय एलान करके रूस और चीन दोनों को निरस्त्रीकरण वार्ताओं की मेज पर लाना चाहते हैं, ताकि अपनी शर्तों पर कोई सौदा कर सकें। हालांकि निष्प्रभावी होती वैश्विक व्यवस्था, खेमों में बंटती दुनिया और बढ़ती असुरक्षा के माहौल में ऐसे एलानों से तीन दशकों पुरानी परमाणु अप्रसार की व्यवस्था टूटकर परमाणु हथियारों की दौड़ भी शुरू हो सकती है। यह दौड़ जहां भारत जैसी उभरती शक्तियों के लिए सिरदर्द बनेगी, वहीं ट्रंप के शांति पुरस्कार के सपने को भी तोड़ सकती है, क्योंकि नोबेल समिति को परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू कराने वाले को पुरस्कृत करने से पहले चार बार सोचना होगा।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)
response@jagran.com

भारतीय राजनीति के कबीर

संबंधों को महत्व देने के गुण के कारण चंद्रशेखर ने भारतीय राजनीति का अधिक मानवीयकरण किया। वे विरोधी विचारधारा वाले राजनेताओं के प्रति भी सद्भाव रखते थे। इसीलिए दूसरे दलों के लोगों के साथ भी उनके व्यक्तिगत संबंध सुमधुर थे।

कृपाशंकर चौबे
वरिष्ठ पत्रकार

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन का एक चौथाई प्रतिशत हिस्सा ही राजनीति केंद्रित था। राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहते हुए भी उनका तीन-चौथाई जीवन व्यक्तिगत संबंधों के निर्वाह में बीता। संबंधों के निर्वाह के मामले में उनका कोई जवाब न था। चंद्रशेखर जी मेरे पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने बलिया के चैनछपरा स्थित गांव आए तो कोलकाता स्थित मेरे आवास पर भी आए। मुझे दो दशकों तक उनकी जो आत्मीयता मिली, वह मेरे लिए धरोहर है। संबंधों को महत्व देने के गुण के कारण चंद्रशेखर ने भारतीय राजनीति का अधिक मानवीयकरण किया। वे विरोधी विचारधारा वाले राजनेताओं के प्रति भी सद्भाव रखते थे। इसीलिए दूसरे दलों के लोगों के साथ भी उनके व्यक्तिगत संबंध सुमधुर थे। चंद्रशेखर कारुणिक मन वाले गंवई खुद्दार राजनेता थे। राजनीति में इस संस्कृति के पैरोकार गांधी, जेपी से लेकर नरेंद्र देव तक थे। आधुनिक राजनीति में चंद्रशेखर अंतिम मानवीय किंतु दृष्टिवान व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय हित में संकटों के समाधान का समावेशी समाधान प्रस्तुत करते थे।

विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर वे बेबाकी से निर्द्वंद्व भाषा में अपनी राय रखते थे। चंद्रशेखर ऐसे जननायक थे जिनके संसद में बोलने के लिए खड़े होने पर देश उत्सुकता से उन्हें सुनने को आकुल हो जाता था। चंद्रशेखर खरी-खरी बोलने के अलावा बेबाक होकर लिखते भी थे। आपातकाल में जब उन्हें जेल में डाल दिया गया तो उन्होंने जेल डायरी लिखी। चंद्रशेखर की जेल डायरी के कई संस्करण निकले। चंद्रशेखर की जेल डायरी से पता चलता है कि चंद्रशेखर ने विश्व के श्रेष्ठ साहित्य का कितना गंभीर अध्ययन किया था। जेल में जो भी किताब वे पढ़ते थे, उसका सार डायरी में लिख लेते थे। चंद्रशेखर का एक बड़ा अवदान यह भी है कि उन्होंने राजनीति को साहित्य-कला-संस्कृति से जोड़े रखा। 'यंग इंडियन' का संपादन उसका छोटा सा सबूत है। चंद्रशेखर ने 1970 में अंग्रेजी साप्ताहिक 'यंग इंडियन' निकाला। 'यंग इंडियन' मार्च 2002 तक चला। बीच-बीच में उसका प्रकाशन स्थगित भी हुआ। 1997 में 'यंग इंडियन' हिंदी में भी निकला। यंग इंडियन में प्रकाशित चंद्रशेखर की संपादकीय टिप्पणियां 'दलीय घेरे के बाहर' शीर्षक पुस्तक में प्रकाशित हुई हैं।

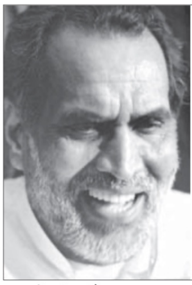

वे इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और विश्वनाथप्रताप सिंह के मंत्रिमंडल में किसी ओहदे पर नहीं थे, फिर भी समानांतर ताकत का केंद्र बने रहे। इसलिए बने रहे क्योंकि इस देश की समस्याओं की जो समझ उनकी थी, वह किसी अन्य राजनेता में नहीं थी

चंद्रशेखर की ये संपादकीय टिप्पणियां उन दिनों देश के सभी बड़े समाचार- पत्रों के पहले पेज की लीड खबर बनती थीं। 'यंग इंडियन' के एक अंक में चंद्रशेखर ने इंदिरा गांधी को परामर्श दिया था कि वे राजसत्ता के मद में संत जेपी से न टकराएं, बल्कि बातचीत का रास्ता अख्तियार करें। चंद्रशेखर तब कांग्रेस में थे किंतु उन्होंने इंदिरा गांधी को दल हित से ऊपर उठ कर राष्ट्रहित के सवाल पर खरी, पर सही राय देने की हिम्मत दिखाई। उसके कुछ दिनों बाद ही चंद्रशेखर के घर लोकनायक जयप्रकाश नारायण चाय पीने आए। वहां कांग्रेस के लगभग 60 सांसद उपस्थित थे। श्रीमती गांधी वहां गए सांसदों से नाराज हुईं तो कुछ कांग्रेसी सांसदों ने बयान दिया कि वे चंद्रशेखर के घर गए अवश्य थे, पर उन्हें मालूम नहीं था कि वहां जेपी आनेवाले हैं। तत्काल चंद्रशेखर का स्पष्टीकरण आया, मेरे अंदर हजार कमियां हो सकती हैं, पर आत्मबल और नैतिक साहस की कमी नहीं है। जेपी के सम्मान में आयोजित पार्टी में आनेवाले सभी सांसद अतिथि जानते थे कि जेपी आ रहे हैं।

चंद्रशेखर की शाश्वत विद्रोही की छवि कभी धूमिल नहीं हुई। पंजाब पर साफगोई से राय व्यक्त करने के कारण बलिया में उन्हें भिडरांवाला कहा गया। तब वे जानते थे कि अपनी इन मान्यताओं के कारण चुनाव हारेंगे, फिर भी पंजाब के सिखों के संदर्भ में उन्होंने अपनी बातें बेबाकी से कहीं। वे वस्तुतः आधुनिक भारतीय राजनीति के कबीर थे। 1985 में चुनाव हारने के बाद कई प्रस्तावों के बावजूद चंद्रशेखर पिछले दरवाजे से संसद में नहीं पहुंचे। 1985 से 1990 के बीच सक्रिय राजनीति के अलावा चंद्रशेखर ने कई सृजनात्मक कार्य किए। सिताबदियारा में जे. पी. स्मारक, करौंधी में राममनोहर लोहिया स्मारक, चंपारण भीतहरवा में गांधी आश्रम का जीर्णोद्धार, आचार्य नरेंद्रदेव के नाम पर स्मृति समारोह, लोगों से एक-एक रुपए लेकर, कमर भर पानी कीचड़ पार करते हुए, खुद ही ईंट उठाते हुए, सफाई करते हुए, आधी रात तक काम करते हुए, उन पावन स्मृतियों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व का उन्होंने पालन किया। इस तरह का दृष्टांत भारतीय राजनीति में विरल है।

वे इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और विश्वनाथप्रताप सिंह के मंत्रिमंडल में किसी ओहदे पर नहीं थे, फिर भी समानांतर ताकत का केंद्र बने रहे। इसलिए बने रहे क्योंकि इस देश की समस्याओं की जो समझ उनकी थी, वह किसी अन्य राजनेता में नहीं थी। चंद्रशेखर ने पदयात्रा कर देश की समस्याओं को निकट से देखा था। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों समेत अपने समय के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में अपने व्याख्यानों तथा 'यंग इंडियन' के संपादकीय के माध्यम से चंद्रशेखर ने पारदर्शी ढंग से विचार किया। वे बराबर बोल और लिखकर याद स्मरण कराते रहे कि हम कैसे मौलिक और बुनियादी सवालों से भटक रहे हैं? राजनीति में यह प्रयास असाधारण था। चंद्रशेखर केवल चार महीने प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल पर नारा बना-चालीस साल बनाम चार महीने। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने तो देश आरक्षण के विरोध में जल रहा था। उनका संक्षिप्त कार्यकाल आग बुझाते ही खत्म हो गया। चंद्रशेखर अयोध्या विवाद का हल भी लगभग निकाल चुके थे।

Pioneer Page No-6

लोक राजनेता-चंद्रशेखर

गरीबी हटाओ के नारे का खोखलापन सबसे पहले जिसने पहचाना वे चंद्रशेखर थे। वे नहीं चाहते थे कि जेपी और इंदिरा गांधी में टकराव हो। लेकिन संपूर्ण क्रांति का रथ जब बढ़ा और चंद्रशेखर को चुनना पड़ा तो परिवर्तनकारी राजनीति के साथ वे खड़े हुए। इमरजेंसी में जेल गए।

राम बहादुर राय
वरिष्ठ पत्रकार

जो चलते तो हैं, पर अपनी राह अलग बनाते हैं। ऐसे विरले राजनेता चंद्रशेखर थे। वे पढ़-लिखकर राजनीति में आए थे। चाहते थे कि राजनीति विज्ञान में पीएचडी करूं। आचार्य नरेंद्र देव ने उन्हें सीधे राजनीति में उतरने की सलाह दी। वे राजनीति में उतरे और चल पड़े। चंद्रशेखर के लिए राजनीति राष्ट्र निर्माण का व्रत बना। जिसे उन्होंने आजीवन निभाया। इस मायने में वे स्वयं बजरिए राजनीति देश के पुनर्निर्माण का विश्वविद्यालय बन गए। स्वाधीन भारत के इतिहास में चंद्रशेखर का स्थान तीन बातों के लिए अमर हो गया है। एक, विचार आधारित जनपक्षीय राजनीति। दो, राजनीति में साहसी प्रयोग के उदाहरण। तीन, प्रधानमंत्री पद पर अनुनय आधारित सौदेबाजी को ठुकरा दिया। वे जो सोचते थे वही करते थे। उसे ही जरूरत पड़ने पर कहते भी थे। इसमें एक जीवन दर्शन है। जिसके चंद्रशेखर आजीवन प्रहरी और प्रवक्ता बने रहे। इसी कारण वे ऐसे राजनीतिक निर्णय ले लेते थे जिसकी आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।

एक बार राजेश पायलट बगावती भंवर में थे। रास्ता पूछने के लिए चंद्रशेखर के पास आए। उनसे पूछा कि आप कांग्रेस में बेहिचक असहमति कैसे प्रकट कर दिया करते थे। चंद्रशेखर जी ने उन्हें समझाया। यह बताया कि ऐसा तुम भी कर सकते हो। लेकिन इसकी एक बड़ी शर्त है। अपने लिए कुछ न चाहो तो हां में हां मिलाने का स्वर मिट जाएगा। उसी से असहमति के लिए हिम्मत अपने आप आ जाएगी। उन्होंने राजेश पायलट को कोरा ज्ञान नहीं दिया। वह उनके आचरण और स्वभाव में रचा बसा था। इस प्रसंग से उनका यह स्वभाव जाना जा सकता है। वे जब कांग्रेस में गए तो कुछ मित्रों ने उनकी भेंट एक दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कराई। इंदिरा गांधी ने पूछा, क्या आप कांग्रेस को समाजवादी मानते हैं? चंद्रशेखर का उत्तर था, लोग ऐसा मानते हैं, मैं ऐसा नहीं समझता। इंदिरा गांधी ने अगला प्रश्न पूछा, फिर कांग्रेस में क्यों आए? चंद्रशेखर ने उनसे नजर मिलाई और प्रतिप्रश्न किया, क्या आप सही उत्तर जानना चाहती हैं? इंदिरा गांधी ने कहा, हां। चंद्रशेखर बोले, कांग्रेस को समाजवादी बनाने की कोशिश करने के लिए मैं आया हूं। इंदिरा गांधी बोल पड़ी, अगर नहीं बनी तो? चंद्रशेखर ने सीधा और बेहिचक कहा, इसे तोड़ने का प्रयास करूंगा। यह संवाद सच है। आज सोच से परे अवश्य लग सकता है। उनमें ऐसा सच कहने का साहस था। गरीबी हटाओ के नारे का खोखलापन सबसे पहले जिसने पहचाना वे चंद्रशेखर थे। वे नहीं चाहते थे कि जेपी और इंदिरा गांधी में टकराव हो। लेकिन संपूर्ण क्रांति का रथ जब बढ़ा और चंद्रशेखर को चुनना पड़ा तो परिवर्तनकारी राजनीति के साथ वे खड़े हुए। इमरजेंसी में जेल गए। तब वे कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य थे। उन दिनों इंदिरा गांधी ने अपना एक भरोसेमंद दूत भेजा। उन्हें लुभाने की वह चाल थी। चंद्रशेखर उसमें नहीं पड़े। इंदिरा गांधी को कहलवाया कि पूरी जिदंगी जेल में कटे यह मंजूर है। तानाशाही नामंजूर है। लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे।

चंद्रशेखर कभी मंत्री नहीं बने। जनता शासन में वे केंद्र में मंत्री बन सकते थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भी यही इच्छा थी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने मंत्री पद पेश किया था। ऐसे चंद्रशेखर को जब समय ने ललकारा तो 35 साल पहले सीधे प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। शासन चलाने की अनुभवहीनता बाधा नहीं बनी। चुनौती बड़ी थी। उसके सामने चंद्रशेखर ने

जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस दिन देश में करीब 75 जगहों पर कर्फ्यू लगा था। आक्रोश और विस्फोटक आंदोलन की गूंज हवा में थी। युवक आत्मदाह कर रहे थे। मंडल आयोग को जिस राजनीतिक ढंग से और जल्दबाजी में लागू किया गया उससे आक्रोश फूट पड़ा था।

खुद को छोटा नहीं समझा। उसे देखा, समझा और खतरों से खेलने का मन बना लिया। उन्हें समस्याएं मिली। मानो वे चंद्रशेखर का बेसब्री से इंतजार ही कर रही हों। जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस दिन देश में करीब 75 जगहों पर कर्फ्यू लगा था। आक्रोश और विस्फोटक आंदोलन की गूंज हवा में थी। युवक आत्मदाह कर रहे थे। मंडल आयोग को जिस राजनीतिक ढंग से और जल्दीबाजी में लागू किया गया उससे आक्रोश फूट पड़ा था। हिंसा भड़क गई थी। दूसरी तरफ सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। अयोध्या विवाद यक्ष प्रश्न बना हुआ था। ऐसे समय में चंद्रशेखर ने शांति, सदभाव और शासन की सार्थकता का बीड़ा उठाया। सामान्य वातावरण बनाने के लिए अपने सहज आत्मविश्वास से कदम उठाए। बड़े निर्णय लिए। उसका चमत्कारित प्रभाव पड़ा। आज सोचकर इस पर किसी को भी अचंभा होगा।

ऐसा भी नहीं था कि लोकसभा में उन्हें बहुमत प्राप्त हो। जनता दल का एक छोटा सा धड़ा ही उनके साथ था। कांग्रेस ने समर्थन घोषित किया। लेकिन संदेह तो पहले ही दिन से था। चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद की जब शपथ ली तो पत्रकारों ने कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी से पूछा कि आप इन्हें कब तक समर्थन देंगे? यह प्रश्न उचित था क्योंकि कांग्रेस का इतिहास वचनभंग का रहा है। राजीव गांधी ने संकेत समझा। और बोले कि कम से कम एक साल। उनके इस कथन में यह निहित था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जो 11 महीने ही चल सकी थी, उससे एक माह ज्यादा वे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को देने का खुलेआम वादा कर रहे थे। क्या उन्होंने अपना वादा निभाया? चंद्रशेखर इसे जानते थे। वे समझते थे कि राजीव गांधी अधिक दिनों तक समर्थन देते नहीं रहेंगे। वे इस भ्रम में भी नहीं थे कि उनकी सरकार लंबी चलेगी।

फिर भी चंद्रशेखर ने सरकार क्यों बनाई? क्या प्रधानमंत्री पद पर सिर्फ अपना नाम दर्ज कराना चाहते थे? क्या उनका वह निर्णय अवसरवादी था? युवा तुर्क के रूप में तूफान उठा देने वाले चंद्रशेखर को सरकार बनाने और चलाने का अनुभव भले ही न हो, पर राजनीतिक सूझबूझ जो उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए दिखाई उससे देश और दुनिया सचमुच दंग रह गई। उनकी ख्याति फैलने लगी। फिर भी यह प्रश्न आज भी अधिक महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सरकार क्यों बनाई। यह प्रश्न मैंने उनसे बहुत बाद में पूछा। चंद्रशेखर की याददाश्त जबरदस्त थी। उन्होंने कहा कि इस विश्वास पर मैंने सरकार बनाई कि परिस्थितियों को सुधारा जा सकता है। मेरा विश्वास था कि देश के लोगों से सही बात कही जाए तो वे पूरा सहयोग करेंगे। कठिनाइयों के बावजूद कोई न कोई रास्ता निकल सकता है, भले ही वह स्थाई न हो।

उस विकट परिस्थिति में कर्तव्य भाव से चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी प्राथमिकताएं तय की। जो निर्णय किए उन पर यह बोझ नहीं दिखता कि सरकार लंबी नहीं चलेगी। वे किसी मानसिक उलझन से परे थे। उनके निर्णयों में स्पष्टता थी। कांग्रेस के दबावों से वे परे थे। वे आक्रोश को शांत कर सके। देश को आर्थिक दिवालियापन से बचा लिया। अयोध्या विवाद को सुलझाने के करीब वे पहुंच गए थे। लालकृष्ण आडवाणी ने लोकसभा में इसे स्वीकारा भी। उनकी ऐसी अनपेक्षित सफलताओं से कांग्रेस बेचैन हो उठी। कांग्रेस के नेता जैसा सोचते थे वैसा न होते देख, चंद्रशेखर की सरकार को गिराने के बहाने खोजने में जुट गए। एक मजाकिया जैसे बहाने से समर्थन वापस लिया। बहाना था कि राजीव गांधी पर हरियाणा के दो सिपाही जासूसी कर रहे थे। चंद्रशेखर ने इस्तीफा देने में क्षणभर भी नहीं लगाया। राजीव गांधी ने दूत भेजे। चंद्रशेखर ने उन्हें लौटाया और अपने निर्णय से यह संदेश दे दिया कि वे सत्ता के लिए समझौते नहीं करते। साबित हुआ कि चंद्रशेखर विचार और आदर्श के लिए राजनीति में आए थे।

Pioneer Page No-6

सोना सिर्फ धातु या बहुमूल्य मुद्रा

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

अर्थशास्त्रियों की सिफारिश है कि भारत को भी सोने के रणनीतिक महत्व को समझना चाहिए और इस पर विस्तृत चर्चा व विमर्श के बाद एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए।

पिछले हफ्ते सोने के कारोबार से जुड़ी दो बड़ी घटनाएं हुईं। एक तरफ, चीन ने सोना खरीदने पर दी जाने वाली टैक्स छूट में कटौती का एलान किया और वहां के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक ने आम ग्राहकों के बेवजह सोना खरीदने पर रोक लगा दी, यानी सोना खरीदना है, तो आपको वजह बतानी होगी। दूसरी ओर, भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 'इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज' में विशेष कैटेगरी ग्राहक के तौर पर सोने के सौदे की बोहनी कर दी। यानी बैंक ने इस एक्सचेंज में अपना पहला सौदा किया।

देखने में शायद ये खबरें बड़ी न लग रही हों, लेकिन इनका असर काफी दूर तक महसूस होगा। चीन काफी समय से सोने पर वैट में छूट देता था, यानी सोने की खरीद को बढ़ावा देता था। चीन में सोने को लेकर एक स्पष्ट सरकारी नीति है। लेकिन भारत में लगभग पचास साल से इस बारे में चर्चा के बावजूद ऐसी कोई नीति नहीं बन सकी। स्टेट बैंक के आर्थिक शोध विभाग ने यह चर्चा एक बार फिर छेड़ दी है। उसकी ताजा रिपोर्ट में यह बात उठाई गई है कि देश को सोने पर एक स्पष्ट नीति की जरूरत क्यों है?

इस वक्त इस बात में जितनी दिलचस्पी है, उतनी शायद पहले कभी नहीं रही, क्योंकि सोने का दाम लगातार बढ़ता दिख रहा है। हालांकि, रिकॉर्डतोड़ तेजी के बाद उसमें कुछ सुस्ती भी दिखी है, लेकिन ज्यादातर जानकार यही कह रहे हैं कि लंबे दौर में तेजी ही रहेगी। पिछले दिनों कैसी तेजी रही, इसका एक नमूना तब सामने आया, जब रिजर्व बैंक ने 'सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड 2017-18' की छठी सीरीज के रिडेंप्शन, यानी आखिरी भुगतान के लिए भाव और तारीख का एलान किया। साल 2017-18 में जारी हुए ये बॉण्ड जिन लोगों ने शुरू में खरीदे थे, उन्हें उस वक्त सोने का भाव 2,961 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से ये जारी हुए। अब रिजर्व बैंक ने इनकी वापसी के लिए सोने का भाव 12,066 प्रति ग्राम तय किया है। चार गुना से भी ज्यादा। यह आठ साल में 307 प्रतिशत का रिटर्न है। ऊपर से छमाही किस्तों में मिला ढाई फीसदी सालाना ब्याज भी जोड़ लें, तो कमाई और तगड़ी हो जाती है।

सोने के दाम में अचानक तेजी की वजह से सिर्फ 'सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड स्कीम' में ही भारत सरकार पर डेढ़ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी बन चुकी है। जिस भाव पर लोगों ने ये बॉण्ड खरीदे हैं, उसे घटाकर भी देखें, तो सरकार करीब 93,000 करोड़ रुपये के घाटे में है। साल 2015-16 के बजट में जब इस योजना का एलान हुआ था, तब इसका उद्देश्य यह था कि सोने के जेवर, सिक्के या बिस्कुट खरीदने के बजाय लोगों को एक ऐसा विकल्प दिया जाए, ताकि उनकी कमाई भी हो सके और उनका पैसा देश के विकास में इस्तेमाल हो सके। लेकिन पिछले साल की शुरुआत में सरकार ने नए बॉण्ड जारी करने बंद कर दिए। वजह बताई नहीं गई, लेकिन जानकारों का कहना है कि सोने के दाम में तेजी और सरकार पर बढ़ता बोझ ही इसकी वजह हो सकती है।

यह पहला मौका नहीं है, जब सरकार ने सोने के व्यापार को नियंत्रित करने की कोशिश की। आजादी से अब तक सरकारों ने सोने को लेकर जो भी कदम उठाए, वे मुख्यतः छह चीजों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। जनता को सोना खरीदने के बजाय निवेश या संपत्ति-निर्माण के दूसरे माध्यमों की तरफ जाने को प्रेरित किया जाए। सोने की सप्लाई पर नियंत्रण रखा जाए। तस्करी पर लगाम लगे। घर-परिवार में सोने की खपत या मांग को कम किया जाए। घरेलू बाजार में सोने के दाम कम रखे जाएं और विदेशी मुद्रा व्यापार व वित्तीय व्यवस्था का संतुलन सुनिश्चित किया जाए।

लेकिन सरकार की स्वर्ण-नीति क्या हो? सरकार सोना कितना और कैसे खरीदे या न खरीदे? भारतीय अर्थव्यवस्था में सोने की क्या जगह हो, इन सब सवालों पर अभी तक स्पष्ट राय नहीं बन पाई है। स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष और उनकी रिसर्च टीम का निष्कर्ष है कि अभी तक की अधिकतर चर्चाएं और सलाहें इस बात पर केंद्रित रही हैं कि कैसे आम आदमी को सोना खरीदने से हतोत्साहित किया जाए। यह दूरंदेशी नहीं थी। जहां कुछ दूरंदेशी दिखाई गई, वहां भी भौगोलिक राजनीति में सोने की महत्ता को रेखांकित नहीं किया गया। जबकि आज की दुनिया में वही सबसे महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। दूसरी बड़ी बात। अभी तक की किसी चर्चा में सोने के कारोबार से जुड़े लोगों की राय को महत्व नहीं दिया गया, जबकि यह कारोबार सीधे या अप्रत्यक्ष तरीके से बहुत बड़ी आबादी को रोजगार दे रहा है।

गौर कीजिए, चीन के सेंट्रल बैंक के खजाने में इस समय 2,300 टन और यहां रिजर्व बैंक के भंडार में 880 टन सोना है। चीन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश भी है और सोने को लेकर उसकी एक स्पष्ट नीति भी है। हालांकि, यह नीति सार्वजनिक नहीं की गई है। तमाम अर्थशास्त्रियों की सिफारिश है कि भारत को भी सोने के रणनीतिक महत्व को समझना चाहिए और इस पर विस्तृत चर्चा और विमर्श के बाद एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। यह तय होना चाहिए कि सरकार सोने को मुद्रा जैसा महत्व देती है या एक सामान्य धातु की तरह ही देखती है। और यह भी कि सोने के खरीदार या आम भारतीय नागरिक के जीवन में सोने का क्या महत्व है?

दिग्गज आर्थिक विशेषज्ञ और कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह का कहना है कि दो चीजों पर नजर रखने से सोने की चाल का अंदाजा हो सकता है। एक तो यह कि सोने की खदानों से कितना उत्पादन हो रहा है और दूसरा यह कि दुनिया के सेंट्रल बैंक कितना सोना खरीद रहे हैं? दुनिया में अभी कुल मिलाकर 2,16,265 टन सोना खदानों से निकाला जा चुका है। और अनुमान है कि लगभग 64,000 टन सोना ही अब धरती के गर्भ में बचा है। अभी तक भारत दुनिया के सबसे बड़े खरीदारों में से है और यहां उत्पादन बहुत कम है। लेकिन हाल में ओडिशा, आंध्र प्रदेश के कई जिलों में सोना मिला है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जीएसआई ने एक नया भंडार खोजा है, जिसमें लाखों टन सोना होने की उम्मीद जताई गई है। यह खोज सोने के पूरे कारोबार को बदलने की ताकत रखती है।

अभी तक सोने की खपत पर रोक लगाने की तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। ऐसे में यह शायद सही मौका है कि सरकार सोने की ताकत को पहचाने और उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बनाए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Hindustan Page No-10

शांति और विकास के लिए विज्ञान जरूरी

आज 'शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस' है। इसके उद्देश्य स्पष्ट हैं- शांतिपूर्ण व स्थिर समाज के लिए विज्ञान की भूमिका को लेकर जागरूकता फैलाना, देशों के बीच विज्ञान को लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना, समाज की बेहतरी के लिए विज्ञान के उपयोग को लेकर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को बनाए रखना और विज्ञान के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर ध्यान लगाना। इस पैमाने पर देखें, तो भारत लगातार विज्ञान की बेहतरी में काम कर रहा है। यहां यही माना जाता है कि समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, और दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व व उसकी प्रासंगिकता से सब कोई वाकिफ है। यह कोई रहस्य नहीं है कि जिसे हम पृथ्वी कहते हैं और अपना घर मानते हैं, उसके बारे में अपनी समझ को व्यापक बनाने और समाजों को और टिकाऊ बनाने में विज्ञान कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए, यह दिवस विज्ञान के विषय पर सभी साझेदारों को एकजुट होने का मौका देता है। अगर भारत की तरक्की देखें, तो बीते साढ़े सात दशकों में विज्ञान के क्षेत्र में हमने खूब विकास किया है। हम स्वदेशी उत्पादन तो करने ही लगे हैं, अंतरिक्ष में भी मंगल तक पहुंच गए हैं। हम संरक्षण की नीति नहीं अपनाते और विज्ञान के मामले में दूसरे देशों की भी दिल खोलकर मदद करते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया के सभी देश भारत को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उम्मीद है, आने वाले दिनों में यह उम्मीद और मजबूत ही होगी।

महिमा कुमारी, टिप्पणीकार

विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, विशेष रूप से भौतिकी की बात करें तो। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज की तरक्की और विकास में भौतिकी की बड़ी भूमिका है। भौतिकी वह विज्ञान है, जिसने हमें ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने का दृष्टिकोण दिया है। न्यूटन के गति के नियमों से लेकर आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत तक, हर खोज ने हमारे जीवन को आसान और बेहतर बनाया है। आज हम जिन सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं- बिजली, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, सैटेलाइट, मेडिकल उपकरण, परिवहन साधन, रोबोटिक्स या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान- इन सबके पीछे भौतिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर बिजली का आविष्कार और उसका उपयोग न होता, तो शायद आधुनिक सभ्यता की कल्पना भी संभव न होती। संचार क्रांति, औद्योगिक क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी का विकास भी भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। यही कारण है कि आज के आधुनिक युग में भौतिकी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है।

अनुपमा कौशल, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

विश्व विज्ञान दिवस

वैज्ञानिक प्रगति में अब भी हम बहुत पीछे

आज पूरी दुनिया तरक्की कर रही है; विज्ञान, तकनीक और नवाचार में नई ऊंचाइयां छू रही है, लेकिन हमारे हिन्दुस्तान में कुछ लोग अब भी जाति और धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। विदेशी मोबाइल, विदेशी कंप्यूटर और विदेशी तकनीक का उपयोग तो सब कर रहे हैं, लेकिन खुद के अंदर कुछ नया बनाने का जज्बा कहीं खो गया है। वे अपने दम पर ऐसी तकनीक नहीं विकसित कर पा रहे कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम विश्व में रोशन हो। आज जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं, तो ज्ञान और सद्भाव की जगह नफरत, गाली-गलौज और हिंसा से भरे वीडियो दिखते हैं। कहीं मार-काट है, कहीं बलात्कार की खबरें, कहीं चोरी के दृश्य- यह सब देखकर शर्म आती है कि क्या यही वह भारत है, जो विश्वगुरु कहलाता था? क्या यही वह सभ्यता है, जहां राम, कृष्ण, बुद्ध और विवेकानंद जैसे महान विचारक पैदा हुए? हमें यह समझना चाहिए कि केवल डिग्रियां लेने से कोई बुद्धिमान नहीं बन सकता। असली समझदारी अपने देश, समाज और तकनीक के विकास में योगदान देने से आती है। जब हम जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं, तब हम वही कर रहे होते हैं, जो कभी अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो' के नाम पर किया था। फर्क बस इतना है कि पहले वे हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाते थे, आज हम खुद अपनी सोच से गुलाम बने बैठे हैं। तय है कि विदेशी तकनीक पर निर्भर रहकर हम कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। आज हम जिस मोबाइल से झगड़ रहे हैं, जिस एप पर एक-दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, वह किसी दूसरे देश- अमेरिका, चीन, जापान या यूरोप की देन है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम वैज्ञानिक प्रगति में अपनी ऊर्जा लगाएं। कोई भी देश सरकारों से नहीं, बल्कि जनता की समझदारी से बनता है। और, जनता तभी समझदार बनेगी, जब वैज्ञानिक चेतना को अपने अंतस में उतारेगी।

स्नेहा राणा दाबोला, टिप्पणीकार

आज की सच्चाई यही है कि दुनिया के दूसरे देश अपनी औद्योगिक व सामरिक ताकत कायम करने के लिए नई तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि भारत ऐसा कोई नवाचार करने के बजाय उनसे कई गुना महंगे दामों में तकनीक खरीद रहा है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि आज हमारे समाज में इतना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो चुका है कि विज्ञान पर नफरत भारी है और बौद्धिक वर्ग हताश। ज्ञान-विज्ञान के अनसुंधान संस्थान बर्बाद हो रहे हैं और तर्क पर धर्म हावी है। इसे रोकना होगा।

राम राज आंबेडकर, टिप्पणीकार

Hindustan Page No-10